भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1489

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

सूचना और प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाएं

1489. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सूचना और प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही कुल योजनाओं की जानकारी है तथा ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं की राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि की जानकारी है;

(घ) पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में सामुदायिक रेडियो आंदोलन समर्थन योजना के अंतर्गत लाभान्वित समुदायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत कोई नई परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए 2019-20 में योजनागत स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन किया। मंत्रालय अब चार केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को कार्यान्वित करता है। मंत्रालय की इन स्कीमों का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जन संचार और सूचना का प्रसार करने के साथ-साथ मनोरंजन और शिक्षा सुनिश्चित करना है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का लाभ देश की पूरी जनसंख्या को समान रूप से मिलता है।

सूचना क्षेत्र में, "विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" स्कीम का उद्देश्य जन कल्याण, राष्ट्रीय एकता का संवर्धन और राष्ट्र निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह प्रभावी और लक्षित पहुंच के लिए प्रिंट विज्ञापन, ऑडियो-विजुअल प्रचार, बाह्य प्रचार, सूचनात्मक ब्रोशर/फ्लायर्स के वितरण, प्रदर्शनियों के दौरान अंतर-वैयक्तिक संचार तथा नए मीडिया माध्यमों जैसे मीडिया माध्यमों का उपयोग कर सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों द्वारा किया जाता है। इस स्कीम के तहत कोई राज्य-विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र में, "फिल्मी सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार (डीसीडीएफसी)" स्कीम का उद्देश्य फिल्म समारोहों, फिल्म बाजारों, फिल्मों के निर्माण और राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत अभिलेखीय फिल्मों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना है। यह स्कीम देश में ऑडियो-विजुअल सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत कोई राज्य-विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है।

प्रसारण क्षेत्र में, "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" स्कीम का उद्देश्य समय-समय पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण अवसंरचना और सामग्री को मजबूत करना है। यह लोक प्रसारक को ट्रांसमीटरों के संवर्द्धन और प्रतिस्थापन, सैटेलाइट प्रसारण उपकरण और डिजिटलीकरण, टीवी चैनलों के विस्तार, एफएम विस्तार के लिए व्यय की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

इस स्कीम के तहत, धनराशि राज्य-वार नहीं अपितु परियोजना-वार जारी की जाती है। प्रसार भारती की प्राथमिकता के अनुसार राज्यों में परियोजनाएं शुरू की जाती हैं और निधियों का परस्पर आवंटन किया जाता है।

इसी प्रकार, प्रसारण क्षेत्र के तहत "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन" स्कीम का उद्देश्य नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को संसाधनों, क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ मजबूत करना है, ताकि प्रचालनरत सीआरएस की संख्या और प्रभावशीलता में वृद्धि हो, जो सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह स्कीम आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन, रेडियो स्टेशनों की क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन, सामग्री निर्माण का समर्थन आदि के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 12 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। इनमें से तीन स्टेशन चित्तूर जिले में, गुंटूर, कडप्पा और पश्चिमी गोदावरी जिले में दो-दो तथा पूर्वी गोदावरी, कुरनूल और श्रीकाकुलम जिले में एक-एक स्टेशन हैं।

मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में कुल 13 कार्यशालाएं, 2 क्षेत्रीय सम्मेलन, 1 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं और विभिन्न सामुदायिक रेडियो केंद्रों को 4 राष्ट्रीय सामुदायिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस स्कीम ने सामुदायिक रेडियो क्षेत्र की अवसंरचना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्षमता निर्माण का संवर्धन कर पूरे भारत में समुदाय को लाभान्वित किया है।

****